Utilisation of Water

1766. SHRI DEBABRATA BISWAS Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the quantum of economically utilisable water available in the country; and

(b) what efforts being made by Government for the development of economically utilisable water for different purposes?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) Out of 4000 cubic kilometres of annual precipitation (snow and rainfall) received by the country, the utilisable quantity of water assessed at present is 1140 cubic kilometres, including 450 cubic kilometres of annual replenishable ground water.

(b) The state Governments are implementing major, medium and minor irrigation schemes for increased utilisation of utilisable water. A total of 263 major irrigation projects and 1104 medium irrigation projects have been taken up so far all over the country in addition to a large number ofwell/tube well irrigation work tanks and other minor irrigation works. Out of these 84 major projects and 778 medium projects have been completed so far. In addition, other measures taken for development of economically utilisable water for different purposes include water-shed development programmes and Command Area Development Programme undertaken since 1974-75. In the light of the National water Policy adopted in September, 1987, establishment of river basin organisations for systematic coordination and management of the river basins has also been planned.

उत्तर प्रदेश की नल कप परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

1767. **श्री राम नरेश यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक नलकूप परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या राज्य सरकार उन शर्तों का पालन कर रही है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक नलकूप परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से प्राप्त सम्बद्ध साख समझौतों (साख संख्या 1004 आई एन, 1332 आई एन और 8 आई एन) में उल्लिखित वित्तीय सहायता के उपयोग के संबंध में शर्तों अनुपत्र में दी गयी हैं **[देखिये]** परिशिष्ट 164, अनुपत्र सं० 32)

(ख) चूंकि उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सार्वजनिक नलकूप परियोजनाए समाप्त कर दी गयी हैं, इसलिए इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इन शर्तों के पालन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना

1768. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या जल ससाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हुई हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपए/लाभ हजार हे टेयर)

क्र० सं० परियोजना का नाम	केंद्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत	लाभ
क. बृहद/बहुप्रयोजनी परियोजनाएं			
I. तकनीकी-आर्थिक जांच पूर्ण परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गई बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों की अनुपालना की जाए।			
1. पुनाती जलाशय परियोजना .	10/89	2609.00	24.29
2. सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना .	7/89	48090.00	245.00
3. सिकिया बराज . .	1/88	11076.00	40.48
4. कोसी बराज की मरम्मत .	2/86	1242.00	—
5. सोन नहर आधुनिकीकरण .	8/83	24700.00	906.00
6. उत्तरी कोइल जलाशय स्कीम .	3/86	43903.00	109.42
II. तकनीकी-आर्थिक जांच पूर्ण लेकिन परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार आस्थगित कर दिया गया।			
1. कोनार सिंचाई परियोजना .	8/88	9361.46	63.83
2. तिलैया बांधर परियोजना .	10/74	4674.00	35.46
III. राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करना अपेक्षित है।			
1. सुखसेनघाट पम्प नहर .	11/89	2061.65	23.19
2. कोसी परियोजना चरण–II .	12/90	8164.40	73.00
3. गन्डक परियोजना चरण–II .	12/90	7882.85	—
4. जमानिया पम्प नहर	11/90	94.87.40	30.06
5. बुरहई जलाशय स्कीम . .	12/90	11249.60	35.00
ख मध्य परियोजनाएं			
I. तकनीकी-आर्थिक जांच पूर्ण परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों की अनुपालना की जाये।			
1. सलैया जलाशय स्कीम	8/83	595.24	2.67
2. रामरेखा जलाशय स्कीम .	8/88	686.00	4.34
3. पनसिंहटरेली जलाशय स्कीम .	8/88	476.20	2.45

(लाख रु.ए/लाभ हजा हेक्टयर)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत	लाभ
4.	सतपोटका जलाशय स्कीम .	8/90	595.00	2.35
5.	कब्बी जलाशय स्कीम . .	8/90	718.34	5.00
6.	कुंडघाट जलाशय स्कीम .	11/82	560.94	1.80

टिप्पण : 1. केन्द्रीय जल आयोग तथा बिहार सरकार के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों ने 28.11.91 को आयोजित बैठक में परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करने संबंधित मुद्दों की पुनरीक्षा की तथा राज्य सरकार द्वारा अनुपालना किए जाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है।

2. परियोजनाओं की निवेश स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है, अन्तर्राज्यीय मुद्दे हल करती है, पर्यावरण, वन तथा पुनर्वास एवं पुनःस्थापन पहलुओं पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है तथा योजना में पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करती है।

Formation of Southern Water Grids

1769. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of WATER RESOURCES ba pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to develop Southern Water Grid;

(b) if so, what are the views of the concerned State Governments in this regard; and

(c) what steps have been taken by Government to co-ordinate the same and the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) National perspective plan for water resources development prepared by the Government, among other links, envisages linking of Mahanadi- Godavari- Krishna- Pen-nar-Cauvery and Pamba-Achankovil-Vaigai for transferring waters from water rich basins to water deficit basins. National Water Development Agency (NWDA), a registered Society under the Ministry of Water Resources has been entrusted with the task of conducting studies to firm up the proposals for optimum utilisation of available waters.

(b) While on the preliminary feasibility reports of Mahanadi-Goda-vari and Godavari-Krishna links, Orissa and Andhra Pradesh have expressed reservations, Kerala expressed their reservations on the preliminary feasibility report of Pamba-Achankovil-Vaigai link.

(c) The , comments/suggestions made by the concerned basin states have been discussed in various forums viz., Technical Advisory Committee, Governing Body and Society meetings of N.W.D.A. to .decide upon the scope of the project.

Clearance of Irrigation Projects

1770. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the details of the irrigation projects cleared by Government for the last one year Statewise and for Maharashtra State in particular;